Institute of Chinese Studies
ICS
中国研究所 DELHI
ANALYSIS

No. 43 November 2016

चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर : ऊर्जा-बिजली परिदृश्य

ऋषप वत्स
रिसर्च इंटर्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज, दिल्ली
rishap.vats@gmail.com

पाकिस्तान लंबे वक्त से बिजली के संकट से जूझ रहा है। पूरे देश में बिजली की कमी है, जबकि साल दर साल इसकी मांग (2.5 फीसदी से लेकर 5 फीसदी की दर से) बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस देश के शासन के लिए बिजली की समस्या का समाधान अहम मुद्दों में शुमार है (Mustafa 2016)। पाकिस्तान के इस बिजली संकट की वजह से ही चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (CPEC) के तहत शुरुआती चरणों की ऊर्जा परियोजनाओं को काफी प्राथमिकता दी जा रही है।

देश में बिजली की मांग और सप्लाई में 2500 से 3000 मेगावाट का अंतर है, जिससे छह से आठ घंटे की लोड शेडिंग आम है (Mustafa 2016)। इसलिए पाकिस्तान के पानी और बिजली मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने बिजली की कटौती को पूरी तरह खत्म करने का जो वादा किया है वो तो इस परिस्थिति में पूरा होता बिल्कुल नहीं दिखता (Business Recorder 2016a) । लेकिन बिजली का मुद्दा राजनैतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के दोबारा चुन कर आने का काफी दारोमदार होगा।

देश में चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर के तहत चीन की ओर से 46 अरब डॉलर निवेश करने की संभावना है। इसमें से 34 अरब डॉलर निवेश अकेले पावर सेक्टर के लिए है। सीपीईसी की परियोजनाओं से 16,400 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है और उम्मीद की जा रही है इससे इसका यह संकट खत्म हो जाएगा (Houreld 2015) । नवंबर 2015 में सीपीईसी कमेटी ने 2018 तक 14 ऊर्जा परियोजनाएं पूरी करने का वादा किया था। लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं (Dawn 2015) ।

पाकिस्तान के पानी और बिजली मंत्रालय के सचिव मोहम्मद युनूस डागा का कहना था कि 2018 तक पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता 30,938

The ICS is an interdisciplinary research institution, which has a leadership role in the promotion of Chinese and East Asian Studies in India. The ICS Analysis aims to encourage debate and provide informed and balanced inputs for policy formulation and is based on extensive research and interactions with a wide community of scholars, experts, diplomats and military personnel in India and abroad.

मेगावाट हो जाएगी। उस दौरान बिजली की मांग 25,961 मेगावाट की होगी लेकिन सप्लाई बढ़ कर 26,590 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। 2017 में 25,080 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जबकि इस दौरान मांग 24,262 मेगावाट की होगी और सप्लाई 21,096 मेगावाट की। लेकिन जून 2016 में बिजली उत्पादन की स्थिति का तीन साल पहले की स्थिति से तुलना करें तो लगेगा कि मोहम्मद युनूस डागा ने वास्तविक स्थिति की पूरी अनदेखी कर यह लक्ष्य निर्धारित किया है।

सीपीईसी की कुछ परियोजनाएं अपने वक्त से काफी पीछे हो गई हैं। उन्हें 'early harvest' कैटगरी से हटा दिया गया है, जबकि कुछ को तो पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

हकीकत यह है कि इस दौरान पाकिस्तान ने सिस्टम में सिर्फ 2665 मेगावाट बिजली जोड़ी है (Dawn 2016c)। पानी और बिजली मंत्री ने नेशनल असेंबली में बिजली परियोजनाओं की रफ्तार पर सवालों का जवाब देते हुए खुद इस वास्तविकता को स्वीकार किया था (Radio Pakistan 2016)।

पाकिस्तान के वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) के मुताबिक जून, 2016 में भरपूर गर्मियों के दिनों में देश ने 9000 मेगावट बिजली की कमी झेली। पूरे देश में आठ घंटे से अधिक की बिजली की कटौती हुई। गांवों में इससे भी ज्यादा बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। हालांकि यह भी सच है कि कुछ हार्वेस्ट प्रोजेक्ट मसलन एर्नगो थार कोल प्रोजेक्ट (सिंध), हुबको कोल प्रोजेक्ट (बलूचिस्तान) और साहीवाल कोल प्रोजेक्ट (पंजाब) पटरी पर हैं और संभवतः 2018 की अपनी समय सीमा में पूरे हो जाएंगे। कई परियोजनाएं देर से चल रही हैं। उन्हें 'early harvest' से 'actively promoted projects' कैटगरी में डाल दिया गया है।

ये पाइपलाइन में हैं या इनके पूरा होने की तारीख 2020 तक बढ़ा दी गई है। कुछ परियोजनाओं पूरी तरह बंद कर दिया है। इनमें बलूचिस्तान का गदानी पावर प्लांट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।

गदानी पावर प्लांट में 9 अरब डॉलर के निवेश से 6,600 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। 2016 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था (The Express Tribune 2015)।लेकिन ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की दिक्कतों और चीन की ओर से इसे पूरा करने की प्रतिबद्धताओं को देखते हुए इसे प्राथमिकता में नीचे रखने और आखिरकार बंद करने का फैसला करना पड़ा (Kiani 2016b)

मौजूदा स्थिति

पिछले साल पाकिस्तान में बिजली की मांग 21,200 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि उत्पादन सिर्फ 16,548 मेगावाट ही था (Mohmmad 2016)। मौजूदा समय में पाकिस्तान की बिजली उत्पादन क्षमता 22,797 मेगावाट है। औसत मांग 17000 मेगावाट के करीब है। उत्पादन और मांग के बीच अब भी 4000 से 5000 मेगावाट का अंतर है। आने वाले वर्षों में यह मांग और बढ़ेगी क्योंकि मुल्क की आबादी हर साल दो फीसदी (Anam 2016) की दर से बढ़ रही है।

अगर पिछले कुछ वर्षों की स्थिति से तुलना करें तो पाकिस्तान में बिजली की सप्लाई और मांग का फासला घटा है। इस दौरान यह फासला घट कर 7500 मेगावाट और 8500 मेगावाट की बीच पहुंच गया है। लेकिन बिजली की सप्लाई बढ़ाने की दिशा में कई ढांचागत समस्याएं बड़ी दिक्कतों के तौर पर सामने आई

हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान बिजली सप्लाई बढ़ाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहा है (The Economist 2012)। उदाहरण के लिए सर्कुलर कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वित्त वर्ष 2015-16 में 30 जून को बिजली विभाग की हासिल रकम बढ़ कर 684.06 अरब रुपये (पाकिस्तानी रुपये) पर पहुंच गई। जबकि इस दौरान इसने 299.06 अरब रुपये का भुगतान किया (Mustafa 2016)।

हालांकि पाकिस्तान सरकार ने हाल में अपने ऊपर बकाये कुछ रकम का भुगतान कर और कुछ कर्जों को माफ कर इस घाटे को 18 फीसदी से घटा कर 17 फीसदी करने में सफलता हासिल की (Mustafa 2016a)। प्रांतीय सरकारों की ओर से बकाये का कुछ हिस्से अदा करने से भी बिजली विभाग की वित्तीय हालत को थोड़ी राहत पहुंची है। इसके अलावा बिजली सेक्टर में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सलाह पर उपभोक्ताओं के लिए बिजली के प्री-पेड मीटर लगाने पर भी विचार कर रही है (Daily Times 2016b)। साथ ही बिजली विभाग की ओर से अदा की जाने वाली रकम में कमी हो इसके लिए एलएनजी (liquid natural gas) का आयात बढ़ाने की योजना बना रही है।

इस तरह सरकार पाकिस्तान के बिजली विभाग पर बढ़ते सर्कुलर कर्ज के बोझ को कम करना चाहती है (The News 2016)। सरकार की इन कोशिशों के नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं। हाल के दिनों में बिजली उत्पादन की लागत में 27 फीसदी की कमी आई है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की ओर से वसूली की दर में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद अगस्त 2016 में हासिल की जाने वाली रकम बढ़ कर 684 अरब रुपये पर पहुच गई। यह अब तक सर्वाधिक स्तर है। (Kiani 2016b) । इन तथ्यों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) ने 2013 में 480अरब रुपये के बकाये का भुगतान कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों की भारी कीमतों की वजह से भी सरकार को तेल सब्सिडी के मोर्चे पर राहत मिली होगी। सस्ते तेल आयात से सरकार की बिजली उत्पादन की लागत भी कम हुई होगी। (kiani 2016d)।

पाकिस्तान के लिए यह बेहद अहम है कि वह सीपीईसी के तहत आने वाले फंड और निवेश इस्तेमाल करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे और खुद को क्षमतावान इकोनॉमिक हब की तरह पेश करे।

हालांकि जनता को लागत में आई इस कमी का लाभ नहीं दिया गया। साथ ही उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल और कुछ सरचार्ज का भी सामना करना पड़ा (kiani 2016d)। इन हालातों की वजह से अब यह सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या सीपीईसी की परियोजनाएं नतीजे देंगी। क्या इनसे पाकिस्तान में बिजली की स्थिति में सुधार होगा। अगर हालात सुधरेंगे भी तो कब तक।

किसी भी हालत में कुछ उपभोक्ताओं की ओर से बिजली बिल बकाया न चुकाने की प्रवृति के बीच क्या पाकिस्तान में बिजली उत्पादन की लागत घटने का इस सेक्टर पर सकारात्मक असर होगा। इन तथ्यों के मद्देनजर

पाकिस्तान में बिजली सेक्टर के हालात जटिल हैं लेकिन अब भी बेहतरी की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगर हाल की रिपोर्टों पर यकीन करें तो पाएंगे कि कई निर्माणाधीन परियोजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की मौजूदा स्थापित बिजली क्षमता में पांच फीसदी की हिस्सेदारी वाला बहावलपुर का सोलर पार्क ऐसी सफल परियोजनाओं में शुमार है। इस पार्क की क्षमता 100 मेगावाट की है और इसमें चीन की जेटीई एनर्जी की ओर से 300 मेगावाट की क्षमता जोड़ी गई है। इसके बाद यह कहा जा रहा है कि यह पार्क पाकिस्तानी की सौर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है (Business standard 2016)।

चीन 2015 में दाईमर भाशा डैम बनाने पर सहमत हुआ था। लेकिन यह एक दूसरे की मुखालफत करने वाले जनजातीय समुदायों के टकराव में फंस गया। एक समुदाय को खैबरपख्तूनख्वा की सरकार समर्थन दे रही है तो दूसरे को गिलगित बाल्टीस्तान की सरकार ।

पनबिजली परियोजनाओं वाले देश के उत्तरी हिस्से के पाक अधिकृत कश्मीर में कोहाला परियोजना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी तरह नीलम-झेलम परियोजना भी सही तरीके से आगे बढ़ रही है और लगता है कि अगस्त 2018 की समय सीमा में पूरी हो जाएगी (Kiani 2016c)। पनबिजली परियोजनाओं में काफी संभावनाएं हैं और लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इसकी क्षमताओं का ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीपीईसी के प्रभारी मंत्री अहसान इकबाल का दावा है कि सीपीईसी के तहत 18 अरब डॉलर कि परियोजनाएं लागू होने के विभिन्न चरणों में हैं और जबकि बाकी 17 अरब डॉलर की परियोजनाओं की तैयारियां चल रही हैं (Aftab 2016)।

पाकिस्तान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सीपीईसी के जरिये दुनिया को यह दिखाए कि उसमें विदेश से आने वाले फंड और निवेश को इस्तेमाल करने की क्षमता है। इसके जरिये उसे दुनिया के मानचित्र पर खुद को एक ऐसी मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की तरह पेश करना होगा, जहां योजनाएं वास्तव में मुकम्मल हो सकती है।

लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस देश में बिजली की भारी कमी हो और अधिकतर शहर अक्सर अंधेरे में डूब जाते हों वहां इन परियोजनाओं को मुकम्मल करना कहां तक संभव है। अगर सीपीईसी के जरिये आने वाले निवेश की बात करें तो इससे पाकिस्तान में जितना फंड आएगा,वह पिछले तीन दशक में बाहर से आए निवेश के बराबर है। सीपीईसी में मुख्य जोर ऊर्जा और इन्फ्रास्ट्रक्चर (अलमीदा 2015) पर है।

सीपीईसी परियोजना के जरिये चीन ने पाकिस्तान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। लेकिन यह प्रतिबद्धता इसकी सफलता की गारंटी नहीं है। सीपीईसी को लेकर सुरक्षा चिंताएं तो हैं ही। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों और संस्थाओं में इसे पूरा करने की क्षमता है। दरअसल, पाकिस्तान को अगर इन परियोजनाओं को मुकम्मल तरीके से पूरा करना है तो उसे कुप्रबंधन और देश के सिस्टम

में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की व्यवस्था से निजात पाना होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन खत्म करने के अभियान के साथ उसकी अपनी दिक्कतें जुड़ी होंगी और इनसे परियोजनाओं में अड़चनें आ सकती हैं। लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार इस बात पर है

पाकिस्तान कैसे अपने इस मौके का इस्तेमाल अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में करता है। अगर पाकिस्तान इसमें सफल रहता है तो यह उसके घरेलू हालातों और विदेश नीति दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

इस बीच, चीन के दबाव और घरेलू असंतोष को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने परियोजनाओं से जुड़े सभी पक्षों को इन्हें जल्द से जल्द समय सीमा के भीतर पूरा करने की चेतावनी दी है या फिर इन्हें सीपीईसी से हटाने का जोखिम मोल लेने को कहा है।

बहरहाल, सीपीईसी की कई परियोजनाओं की शर्तों और नियमों में पारदर्शिता की कमी सामने आई है उसने पाकिस्तान और इसके बाहर दोनों जगह इसके बारे में आशंकाओं और धारणाओं को जन्म दिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार कुछ परियोजनाओं में तेजी लाकर यह दिखाने की कोशिश में है कि सीपीईसी परियोजनाओं को पूरा करने के मामले में माहौल सकारात्मक है।

ऊर्जा परियोजनाओं के सामने खड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उत्साही हैं और उन्होंने कहा है तमाम अड़चनों और बाधाओं के बावजूद बिजली परियोजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 1 सितंबर 2016 को ग्वादर में एक साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश की कुछ बिजली परियोजनाएं अगले साल के मध्य तक पूरी हो जाएंगी और 2017 के आखिर तक देश में देश में बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता बढ़ कर 10000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। हमें उम्मीद है कि 2018 तक देश में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी (Dawn 2016)।

शुरुआती दिक्कतें

अगर सीपीईसी की अलग-अलग परियोजनाओं से जुड़ी खबरों और ताजा जानकारियों पर गौर करेंगे तभी आप इस परियोजना की प्रगति का समग्र जायजा ले पाएंगे। अगर आप इन टुकड़े-टुकड़े जानकारी जोड़ कर देखें तो तो आपको इस परियोजना की काफी साफ तस्वीर दिखेगी। मसलन,जिन बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं को बिजली संकट के समाधान के तौर पर पेश किया गया, वे बेहद देरी की शिकार हैं। जैसे, सिंध में कासिम बंदरगाह की कोयला परियोजना। इससे 1320 मेगावाट बिजली हासिल करने की उम्मीद है लेकिन यह भूमि अधिग्रहण विवाद की वजह से यह केंद्र और प्रांतीय सरकार के बीच झगड़े का कारण बन गया है। अभी तक भूमि अधिग्रहण विवाद सुलझ नहीं पाया है (kiani 2016C)। सुकी किनारी पनबिजली परियोजना में भी यही हुआ। खैबर पख्तुनख्वा के मनशेरा जिले की परियोजना सीपीईसी की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक थी लेकिन वहां भूमि अधिग्रहण से जुड़ा विवाद चल रहा है (The Express Tribune 2016a,c)।

चीन की गेझोउब समूह की ओर से बनाए गए इस बांध से 870 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी लेकिन 1.8 अरब डॉलर की यह परियोजना एक साल पीछे हो गई है। इसे लेकर केंद्र और हखैबर पख्तूनख्वा सरकार के बीच जो टकराव चल रहा है, उससे भी परियोजना में देरी हो रही है। टकराव की इस स्थिति में अभी इसके और देरी की आशंकाएं हैं। पिछले दिनों खैबर पख्तूख्वा के मुख्यमंत्री परवेज खटक ने केंद्र सरकार पर खुलेआम राज्यों की बिजली चुराने का आरोप लगा दिया (Daily Times 2016a)।

दाईमर भाशा बांध सीपीईसी परियोजना का हिस्सा नहीं है। बांध के एक हिस्से का निर्माण गिलगिट बाल्टीस्तान के गंदलो नाला इलाके में होना था। इसे चीन 2015 में बनाने को राजी हुआ था। लेकिन वह भी प्रतिद्वंदी जनजातीय समुदायों के बीच फंस गया है (The News 2015)।

खैबरपख्तूनख्वा में कोहिस्तान की सीमा और गिलगित बाल्टीस्तान में दाईमर की बीच की जमीन पर पिछले दिनों एक दूसरे के विरोधी जनजातीय समुदायों के बीच कई टकराव हो चुके हैं। इनमें से कुछ को खैबरपख्तूनख्वा सरकार तो कुछ को गिलगित बाल्टीस्तान सरकार समर्थन दे रही हैं (Mohammad 2016b)।

परियोजना से 4500 मेगावाट बिजली सप्लाई की उम्मीद है और इससे नदी में कम पानी प्रवाह के दौरान सिंचाई के लिए 7.89 अरब घन मीटर जल भंडारण होगा। इसे पाकिस्तान के ऊर्जा संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। हालांकि संघीय सरकार की कैबिनेट ने 10 सितंबर 2016 को बांध निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण और इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा जारी करने को मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके बावजूद यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि जमीन पर इस परियोजना को कोई गति मिल पाएगी (Ahmed 2016)।इस परियोजना को 2016 में पूरा करने का लक्ष्य था। यह बेहद अहम परियोजना है क्योंकि इससे सिंचाई में मदद मिलेगी। बाढ़ का खतरा कम होगा और इससे तारबेला बांध की जिंदगी और 35 साल बढ़ जाएगी (Zaafi 2016)।

पाकिस्तान ने रिवॉल्विंग फंडों का गठन कर सीपीईसी की परियोजनाओं को लेकर चीनी सरकार और निवेशकों की चिंता दूर करने की कोशिश की है। इन फंडों को पाकिस्तान सरकार की सॉवेरन गारंटी मिली हुई है।

जमीन अधिग्रहण और जनजातीय समुदायों के बीच टकराव से जुड़ी समस्याओं के अलावा परियोजना को अब वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। जब परियोजना के लिए भारी फंड की जरूरत पड़ी तो इसके शीर्ष फाइनेंसर एडीबी (Asian Development Fund) ने पैसा देने के बारे में किसी वादे से इनकार कर दिया (Kiani 2016a)।

इस बीच सीपीईसी की कई परियोजनाओं को ‘Early Harvest’ की समय सीमा (first phase) की कैटेगरी से निकल कर ‘actively promoted’ कैटगरी में ले आया गया है। परियोजनाओं में देरी ने पाकिस्तान सरकार में बैठे लोगों को सतर्क कर दिया है। चीन के दबाव और घरेलू असंतोष को देखते हुए

पाकिस्तान सरकार ने परियोजनाओं से जुड़े सभी पक्षों को इन्हें जल्द से जल्द समय सीमा के भीतर पूरी करने की चेतावनी दी है या फिर इन्हें सीपीईसी से हटाने का जोखिम मोल लेने को कहा है (Rana 2016b)। इन देरियों की वजह से पानी और बिजली मंत्रालय ने कई परियोजनाओं की समय सीमा तय कर दी। उसने थार ब्लॉक-2 प्रोजेक्ट, जिसमें एनग्रो थार पावर प्लांट की ओर से 1320 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी, को दिसंबर, 2018 तक पूरा कर लेने को कहा है। इसी तरह साइनो-सिंध पावर प्लांट को भी चेतावनी जारी की गई है। प्लांट से कहा गया है कि वह निर्माण कार्य शुरू करे या फिर प्राथमिकता वाली योजनाओं की श्रेणी से नीचे जाने का जोखिम मोल ले। प्लांट से कहा गया है कि उसे 'actively promoted' कैटगरी से हटाया जा सकता है। स्थिति ज्यादा खराब हुई तो उसे कोरिडोर से ही हटाया जा सकता है। (Rana 2016b)

ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में फंड और सीपीईसी परियोजनाओं के आवंटन और उन्हें पूरा करने को लेकर प्राथमिकताओं में भी अंतर है।

जमीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद और धीमी क्लीयरेंस के अलावा हर परियोजना को कभी न कभी टैक्स राहत और छूटों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सरकार ने इन परियोजनाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई उपाय किए हैं। मसलन कुछ सीपीईसी परियोजनाओं के ठेके लिए बोली (bidding) की शर्तों में छूट दी गई हैं। कुछ को सॉवरेन गारंटी दी गई है। यह सब चीनी निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए किया गया ताकि वे परियोजनाओं से अपने हाथ न खींचे।च चीनी निवेशकों को सबसे ज्यादा टैक्स छूट के जरिये आकर्षित किया गया। लेकिन अब भी टैक्स राहत और छूटों से जुड़ी कई समस्याएं अनसुलझी हैं। जैसे, परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लांट और मशीनरी के आयात पर टैक्स छूट (कासिम बंदरगाह परियोजना) का मामला। शुल्क (tarrif) समझौतों के लंबित मामले (पंजाब में साल्ट रेंज बिजली परियोजना से संबंधित)। इसके अलावा कई परियोजनाओं के लिए कोयले की उपलब्धता भी काफी चुनौतीपूर्ण मसला बना हुआ है (Kiani 2016c)।

सीपीईसी की मौजूदा परियोजनाओं में आ रही दिक्कतों को सुलझाने और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) और चीनी अधिकारियों ने 29 जून 2016 (Sarfarz 2016) को बैठक की।

हालांकि ग्वादार पोर्ट अथॉरिटी (GPA) की मुश्किलें बरकरार हैं। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी को अब भी अंदाजा नहीं मिल पा रहा है कि परियोजना (Swad-gwadar city water supply) को सरकार के अनुदान से पूरा किया जाए या ब्याज मुक्त कर्ज के जरिये या फिर चीन से कॉमर्शियल लोन लेकर। सीपीईसी परियोजनाओं में ऐसी उलझन और भ्रम बने हुए हैं (Kiani 2016c)। जहां तक कोयला आधारित परियोजनाओं का सवाल है तो वहां पानी की भारी जरूरत है। (प्रति टन कोयले के लिए 10 से 150 गैलन पानी की जरूरत पड़ती है) । दरअसल पाकिस्तान में कोयले के खनन के लिए ज्यादातर स्ट्रिप माइनिंग विधि का इस्तेमाल होता है। कोयला खनन से जुड़ी

परिचालनों के लिए पानी की सप्लाई बेहद जरूरी है। इसलिए पानी सप्लाई से जुड़ी परियोजना में देरी से सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं को समय से पूरा करना मुश्किल है।

सरकार आने वाले चुनावों के मद्देनजर परियोजनाओं में देरी से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने पर जोर दे रही है। वह परियोजनाओं की प्राथमिकता बदल रही है। जुलाई 2016 में पंजाब की बिजली सप्लाई के लिए निर्धारित सिंध की दो कोयला परियोजनाओं का दर्जा घटा दिया गया। इसकी जगह पर एलएनजी आधारित 3600 मेगावाट की तीन बिजली परियोजनाएं प्राथमिकता सूची में जोड़ दी गईं। परियोजनाओं की प्राथमिकता श्रेणी में यह कह कर बदलाव किया गया कि इससे ये समय पर पूरी होंगी। इसके अलावा योजना और विकास मंत्री अहसान इकबाल ने भी कहा कि ट्रांसमिशन लाइन का न होना भी सिंध की परियोजनाओं की प्राथमिकता श्रेणी में बदलाव का कारण बना (Rana 2016d)। यह नॉर्थ-साउथ ट्रांसमिशन लाइन टर्नओवर पर अधिकतर टैक्स और दस साल के लिए अल्टरनेट कॉरपोरेट टैक्स के साथ ही टैरिफ से जुड़े मुद्दों से जूझ रही है। और अब इस देरी के लिए इसके प्राथमिकता सूची से पूरी तरह हटने का खतरा पैदा हो गया है (Kiani 2016c)।

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के कंट्री मैनेजर वर्नर लिपैक ने हाल ही में कहा था कि एडीबी 'मोटे तौर पर इन परियोजनाओं की प्रगति से संतुष्ट है।, सरकार की कोशिशें अगले दो साल में देश में बिजली की राशनिंग जैसी समस्या को खत्म कर सकती है (The Wire 2016)। भले ही एडीबी के कंट्री मैनेजर आशावादी रुख रखते हों लेकिन परियोजनाओं को लेकर सरकार के समग्र नजरिये में बुनियादी खामियां हैं। सीपीईसी से जुड़ी बिजली परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है खास तौर पर उस स्थिति में जब देश में बिजली की मांग भी बढ़ रही है और वितरण की स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर ट्रांसमिशन लाइनों को अपग्रेड करने और ट्रांसमिशन लाइनों की खराबियों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई तो परियोजनाओं के दूसरे मोर्चों पर हासिल सफलताओं का कोई फायदा नहीं होगा।

ट्रांसमिशन की खराबी की वजह से बिजली बर्बादी, डिफॉल्ट की अनदेखी और बिजली की भारी चोरी मिल कर देश में बिजली सप्लाई की दिक्कतों को और बढ़ा देती हैं। खराब ट्रांसमिशन की वजह से बिजली सप्लाई को होने वाले नुकसान और बिजली चोरी का स्तर बढ़ कर 17.9 फीसदी पर पहुंच चुका है और इससे 2015-16 में पाकिस्तान को 29 अरब रुपये (पाकिस्तान रुपया) का घाटा हुआ है।

पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के पूर्व प्रबंध निदेशक (Managing Director) ताहिर बशारत चीमा का कहना है कि पकिस्तान में जितनी बिजली का उत्पादन और वितरण होता है उसके 20 फीसदी का नुकसान सिस्टम में हो ही जाता है। पांच फीसदी बिजली सिस्टम से चुरा ली जाती है। बिजली उत्पादन और वितरण का सिस्टम पुराना पड़ जाने का वजह से भी और पांच फीसदी का नुकसान हो जाता है। दस फीसदी टेक्निकल लॉस में चली जाती है। हालांकि यह पाकिस्तान के बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर के आकार के हिसाब से नगण्य है (Rizvi 2016)। इसलिए जब तक पाकिस्तान

अपने मौजूदा ट्रांसमिशन नेटवर्कों की क्षमताएं और कार्यकुशलता नहीं बढ़ाता तब तक नेशनल ग्रिड की क्षमताएं बढ़ाने का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा।

यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने सीपीईसी परियोजनाओं में देरी की वजहों का आर्थिक हल निकाल लिया तो हो सकता है कि चीन की ओर से भारी मात्रा में आने वाला फंड रुक जाए। हालांकि ऐसा किया गया तो यह इस विशाल परियोजना का रणनीतिक पहलू उपेक्षित हो जाएगा। अगर चीन सीपीईसी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी का तलबगार है तो उसे भी अपनी ओर से कुछ बलिदान करना होगा ताकि पाकिस्तान अपनी व्यवस्था में सुधार कर सके। और शायद चीन इस पहलू को अच्छी तरह समझता भी है।

हालांकि सीपीईसी परियोजनाओं को लेकर भारी घाटा और धीमी प्रगति से चीनी निवेशकों को चिंता हो सकती है इससे भविष्य में चीनी निवेश में अड़चनें पैदा हो सकती है लेकिन चीन शायद ही पाकिस्तान जैसे अपने सदाबहार दोस्त को इतनी आसानी से छोड़ेगा।

यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने कमाई और खर्च का अंतर नहीं पाटा तो सीपीईसी परियोजनाओं का भविष्य अंधकारमय बना रहेगा। पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े पाकिस्तानी व्यवसायियों और कारोबारी समुदाय ने सरकार से सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने की अपील की है ताकि उनका देश इसमें किए गए निवेश का भरपूर इस्तेमाल कर सके (Daily times 2016C)।दरअसल, पाकिस्तान में बिजली सेक्टर में सर्कुलर कर्ज का जो भारी बोझ है उसकी वजह इस क्षेत्र के सरकारी प्रतिष्ठान हैं। इन्हें इस देश का संभ्रांत वर्ग चलाता है और अगर इनके निजीकरण की कोशिश हुई तो इसका भारी राजनीतिक विरोध होगा। लेकिन चीन की ओर से परियोजनाओं को पटरी पर लाने के दूसरे तरीकों के बारे में सोचने के साथ ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है पाकिस्तान में यह सरकारी रवैया कब तक चलेगा। पाकिस्तान के अंदर इस हालात से चीन सरकार और वहां के निवेशक चिंतित है। लिहाजा पाकिस्तान ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इससे चीन कुछ हद तक आश्वस्त हो सकता है।

चीन को भरोसा दिलाने वाले कदमों के तहत पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी समर्थित रिवॉल्विंग फंडों की स्थापना की है। साथ ही वह कई औद्योगिक पार्क और मिनरल प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की भी योजना बना रहा है (Dawn 2016a)। इसके साथ ही इस साल जून से शुरू नए नियम के तहत सभी मंत्रालय, सरकारें (प्रांतीय सरकारें)और विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में शामिल की जाने वाली सीपीईसी परियोजनाओं में आने वाली अड़चनों का ब्योरा पेश करेंगे। अगले वित्त वर्ष में शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों के लिए ऐसा करना जरूरी है ताकि इनकी प्रगति के आधार पर इन्हें फंड सुनिश्चित किया जा सके (Sarfaraz 2016)। पाकिस्तान सरकार का यह कदम कारगर हो सकता है लेकिन उसे इन परियोजनाओं के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दीर्घकालिक असर और देनदारियों को चीनी निवेशकों को मुनाफा लौटाने के बारे में भी सोचना होगा।

गहराते राजनीतिक मतभेद

चीनियों की नजर में आर्थिक विकास देश में शांति बनाए रखने का उनका पसंदीदा तरीका है। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन के महत्वाकांक्षी प्रयास के तौर पर सीपीईसी ने पाकिस्तान की राजनीति में विभाजन को और तीखा कर दिया है। सीपीईसी के रूट को लेकर विवाद के अलावा एक बड़ा झगड़ा इससे जुड़ी परियोजनाओं में संसाधन के असमान बंटवारे को लेकर भी है। सीपीईसी परियोजनाओं को लेकर एक बड़ा आरोप यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में फंड और सीपीईसी परियोजनाओं के आवंटन में गैर बराबरी है। यही नहीं उन्हें पूरा करने की प्राथमिकताओं में भी अंतर रखा गया है।

यह भी दिलचस्प है सीपीईसी परियोजनाओं से पैदा होने वाली कुल बिजली में से 4,4210 मेगावाट बिजली सिंध में, 3640 मेगावाट पंजाब में, 960 मेगावाट बलूचिस्तान में, 870 मेगावाट खैबर पख्तूनख्वा में और 720 मेगावाट पाक अधिकृत कश्मीर में पैदा होगी (Business Recorder 2016b)। संसद में जो आंकड़े पेश किए गए हैं कुल परियोजनाओं का 53 फीसदी पंजाब को आवंटित किया गया है। कुल 330 परियोजनाओं में 176 पंजाब को आवंटित किए गए हैं (Qadeer 2016)। राज्यों के बीच परियोजनाओं के इस असमान बंटवारे ने इन आरोपों को बल दिया है कि पंजाब को तवज्जो दी गई है। आने वाले चुनावों के मद्देनजर पंजाब में ज्यादा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।

खैबर पख्तूनख्वा और केंद्र सरकार के बीच टकराव तो जगजाहिर है। लेकिन परियोजनाओं के खिलाफ बलोच खास कर क्षेत्रीय पार्टियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। अभी तक सीपीईसी की आठ परियोजनाएं बलूचिस्तान को आवंटित की गई हैं। लेकिन ग्वादार के रणनीतिक महत्व को देखते हुए और क्षेत्र में अस्थिरता के मद्देनजर ये परियोजनाओं आगे चल कर केंद्र सरकार के लिए भारी सिरदर्द पैदा कर सकते हैं।

ऐसा ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर सीपीईसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जा सकता है।

केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इन इलाकों और संघीय प्रदेशों, दलों और लोगों के बीच किसी भी तरह की उपेक्षा की भावना को दूर करे। इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक विभाजन अच्छे संकेत नहीं हैं और इससे परियोजना को लेकर देश और विदेश, दोनों जगर चिंता लाजिमी है। 11 सितंबर को चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अंतरराष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री झेंग जियोओसोंग ने बीजिंग में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक शिष्टमंडल से मुलाकात में परियोजना से जुड़े इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सीपीईसी जैसी परियोजनाओं की क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए एकजुटता और राजनीतिक सहमति जरूरी है।

बहरहाल, परियोजनाओं के विरोधियों के खिलाफ पाकिस्तान जिस तरह से आतंकरोधी कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है वह इसका

हल नहीं है। इस तरह के कदम का काफी उल्टा असर हो सकता है। 2016 के अगस्त महीने में गिलगित इलाके में परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना ने कम से कम 500 युवाओं को अपने कब्जे में लिया (ANI 2016)। ऐसे टकराव परियोजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों को जाहिर करते हैं। परियोजनाओं को लेकर केंद्र के इस तरह के सख्त रवैये से राज्य सरकारें नाराज हैं। इस तरह की सख्ती के खिलाफ उन्होंने अपने ढंग से प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अभी तक इन परियोजनाओं के लिए विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती के अधिकार केंद्र को नहीं दिए हैं (The Express Tribune 2016b)।

सीपीईसी परियोजनाओं में काम कर रहे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चीनियों के बीच सुरक्षा चिंता बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही परियोजनाओं की धीमी गति को लेकर भी बेचैनी बढ़ रही है। ये हालात चीन को दूसरे विकल्प आजमाने की ओर प्रेरित कर रह हैं। हाल में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आईं थीं जिनमें यह कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना के सहयोग से सीपीईसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जा सकता है। हालांकि नेतृत्व (नागरिक नेतृत्व) ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है या ऐसी किसी योजना से इनकार कर रही है (Siddique 2016)।

अगर सीपीईसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे किसी नए संगठन का गठन किया जाता है तो इससे सैन्य और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के तनावपूर्ण रिश्तों में और खिंचाव पैदा होगा। अथॉरिटी के गठन जैसी बातों को लोगों के बीच इस धारणा से बल मिला है कि सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) निर्बाध बिजली सप्लाई के अपने वादे को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। जबकि नवाज की पार्टी को सत्ता दिलाने में बिजली की कमी को पूरा करने के वादे ने भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन लगता है यह नवाज सरकार के पतन की भी अहम वजह बन सकती है। अगर पाकिस्तान की सेना और सरकार के बीच सीपीईसी के मुद्दे पर तनाव बढ़ता है तो यह चीन के लिए और भी बुरा होगा। यह टकराव सुरक्षा को लेकर अड़चन पैदा करेगा और इससे परियोजनाओं को समय से पूरा करने में देरी हो सकती है।

निष्कर्ष

इस पेपर में सीपीईसी को लेकर जिन कठिनाइयों की चर्चा की गई है उनके बावजूद पाकिस्तान के अंदर आशावादी रवैया है. पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को लगता है कि सीपीईसी इससे उनका देश इलाके के भू-राजनैतिक हालात में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा. इससे आर्थिक समृद्धि के वाहक दक्षिण एशिया, चीन और मध्य एशिया जुड़े जाएंगे (Aftab 2016)। और पाकिस्तान को अपनी मजबूत जियो-पॉलिटिकल का लाभ जियो-इकोनॉमिक हालात को दुरुस्त करने में मिलेगा. पाकिस्तान के इनवेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिफताह इस्माइल ने दावा किया है कि सीपीईसी में 150 अरब डॉलर का निवेश आएगा. सीपीईसी की परियोजनाओं में निवेश करने वाली कंपनियों के वादों के आधार इतनी बड़ी रकम का अंदाजा लगाया गया है. अगर यह दावा सही है तो सीपीईसी से लगाई गई बड़ी उम्मीदें सही साबित हो सकती हैं (Aftab 2016)। यहां तक कि तुर्की और ईरान ने भी

सीपीईसी में शामिल होने और इसका फायदा उठाने की उम्मीद जताई है (Aftab2016)।

अहसान इकबाल ने तो ईरान और सऊदी अरब का स्वागत करते हुए कहा है कि अगर ये दोनों देश सीपीईसी (Dawn 2016a) का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनका स्वागत है. भाई समान दोनों इस्लामी देशों का हम स्वागत करेंगे. ईरान और सऊदी अरब देशों की ओर से सीपीईसी के बारे में इस तरह के रुख से पाकिस्तान के और बेहतरीन मौके पैदा होते हैं. इससे पाकिस्तान को अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करने का मौका मिलेगा. और वह इस तरह के कदम उठा सकेगा, जिससे दुनिया के सामने पाकिस्तान की छवि सकारात्मक होकर उभरे. हालांकि सीपीईसी परियोजनाओं में होने वाली देरी पाकिस्तान में बिजनेस के माहौल को जबरदस्त ढंग से चोट पहुंचा सकती है. साथ ही यह इसे लेकर चीन की योजनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है. बहरहाल इस क्षेत्र और ग्लोबल स्तर पर चीन की महत्वाकांक्षाएं और सामरिक-रणनीतिक हित काफी कुछ इस बेहद महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता पर निर्भर करती है.

ओबीओआर जैसी विशाल परियोजनाएं और भविष्य को ध्यान में रख कर बनाई गई कागज पर तो 19 वीं सदी के 'ग्रेट गेम' रणनीति का अहसास दिलाती हैं लेकिन इसके जल्द सकारात्मक नतीजों की फिलहाल चीन को तो नहीं लेकिन पाकिस्तान को बेहद जरूरत है. चीन के समुद्री सिल्क रूट में सीपीईसी ग्वादर के जरिये बेहद अहम रोल निभाएगा. सीपीईसी में निवेश पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करने के चीन के मार्शल प्लान से आगे बढ़ कर भी बहुत कुछ है. सीपीईसी चीन के ब्लेट एंड रोड इनिशिएटिव की अहम फ्लैगशिप परियोजना है. चीन की यह पहल काफी हद तक चीन और दूसरे देशों को साफ है और सकारात्मक संदेश देने वाली है.

सीपीईसी एक ऐसी सहायक परियोजना है, जिसकी सफलता या असफलता का असर बेहद अहम होगा. अगर यह मिशन सफलता रहता है तो योजना को वास्तविकता में बदलने के चीन की क्षमता को एक नई दृष्टि से देखा जाएगा. अगर पाकिस्तान में स्थिरता आती है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ चीन को ही मिलेगा. पाकिस्तान में स्थिरता का काफी कुछ दारोमदार उन ऊर्जा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने पर निर्भर होगा, जो सीपीईसी के जरिये खड़ी होने वाली हैं. ये परियोजनाएं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बदलाव की वाहक होंगी. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इसके जबरदस्त सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. ऊर्जा परियोजनाओं की सफलता से न सिर्फ पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती मांग पूरी सकेगी बल्कि इससे उद्योगों की भी जरूरत पूरी होगी. साथ ही यह सीपीईसी रूट से लगी विकास परियोजनाओं की भी ऊर्जा जरूरत पूरी कर सकेगी.

पाकिस्तान की आर्थिक तस्वीर बदले से चीन को भी विश्व मंच पर एक भरोसेमंद, मजबूत और क्षमतावान दोस्त हासिल होगा. चीन की इस हकीकत को समझता है. लेकिन इसके पहले उसे पाकिस्तान को अंधेरे से निकालना होगा.

संदर्भ

Aftab, M. 2016. 'CPEC set to attract $150b investment in Pakistan', *Khaleej Times*. 11 September, http://www.khaleejtimes.com/business/economy/cpec-set-to-attract-150b-investment-in-pakistan (accessed on 11 September 2016).

Ahmed, Amin. 2016. 'Diamer-Bhasha dam land acquisition plan approved', *Dawn*. 10 September, http://www.dawn.com/news/1283195/diamer-bhasha-dam-land-acquisition-plan-approved (accessed on 11 September 2016).

Almeida, Cyril. 2015. 'Chinese Whispers', *Dawn*. 19 April, http://www.dawn.com/news/1176805 (accessed on 24 August 2015).

Anam, Zeb. 2016. 'Pakistan's energy crisis', *Daily Times*, 14 April http://dailytimes.com.pk/opinion/14-Apr-16/pakistans-energy-crisis (accessed on 24 August 2016).

ANI. 2016. 'Protestors to be charged under Anti-terrorism law: Pak on CPEC row' 18 August http://www.aninews.in/newsdetail-MzU/Mjc2NDcw/protestors-to-be-charged-under-anti-terrorism-laws-pak-on-cpec-row.html (accessed on 5 September 2016).

Business Recorder. 2016a. 'Load shedding will end by 2018: Asif', 10 June, http://www.brecorder.com/fuel-a-energy/193:pakistan/55390:loadshedding-will-end-by-2018-asif/?date=2016-06-10 (accessed on 24 August 2016).

Business Recorder. 2016b. 'CPEC's early harvest projects to complete by 2017-18', 22 August, http://www.brecorder.com/top-news/pakistan/315014-cpecs-early-harvest-projects-to-complete-by-2017-18.html (accessed on 5 September 2016).

Business Standard. 2016. 'China-Pakistan economic corridor on track, says Chinese diplomat', 25 June, http://www.business-standard.com/article/international/china-pakistan-economic-corridor-on-track-says-chinese-diplomat-116062500466_1.html (accessed on 25 August 2016).

Daily Times. 2016a. 'Centre versus the provinces', 13 July http://dailytimes.com.pk/editorial/13-Jul-16/the-centre-versus-the-provinces (accessed on 26 August 2016).

Daily Times. 2016b. 'ICCI asks govt to introduce prepaid electricity meters' 26 April http://dailytimes.com.pk/business/26-Apr-16/icci-asks-govt-to-introduce-prepaid-electricity-meters (accessed 20 August 2016).

Daily Times. 2016c. 'Traders want early completion of CPEC-related projects', 25 July http://dailytimes.com.pk/business/25-Jul-16/traders-want-early-completion-of-cpec-related-projects (accessed on 1 September 2016).

Dawn. 2015. 'Govt to complete 14 energy projects by 2018, CPEC committee told' 18 November , http://www.dawn.com/news/1220544/govt-to-complete-14-energy-projects-by-2018-cpec-committee-told (accessed on 26 August 2016).
Dawn. 2016a. 'ECC approves plan to set up special funds for CPEC projects', 19 February http://www.dawn.com/news/1240546 (accessed on 26 August 2016).

Dawn. 2016b. 'Pakistan will welcome Iran, Saudi if they want to be part of CPEC: AhsanIqbal', 2 October, http://www.dawn.com/news/1287552/ (accessed on 10 October 2016).

Dawn. 2016c. 'PM inaugurates CPEC projects in Gwadar', 1 September, http://www.dawn.com/news/1281350 (accessed on 7 September 2016).

Ghauri, Irfan. 2016. 'China calls for consensus on CPEC', *The Express Tribune*. 11 September. http://tribune.com.pk/story/1180337/china-calls-consensus-cpec/ (accessed on 11 September 2016).

Houreld, Katharine. 2015. 'China and Pakistan launch economic corridor plan worth $46 billion', Reuters. 20 April, http://www.reuters.com/article/us-pakistan-china-idUSKBN0NA12T20150420 (accessed on 24 August 2016).

Kiani, Khaleeq. 2016a. 'ADB refuses to fund mega dam project', Dawn. 27 October http://www.dawn.com/news/1292536/adb-refuses-to-fund-mega-dam-project (accessed on 30 September 2016).

Kiani, Khaleeq. 2016b. 'Country's power bill touches highest mark', *Dawn. 22* August http://www.dawn.com/news/1279114 (accessed on 8 November 2016).

Kiani, Khaleeq. 2016c. 'CPEC: teething problems', *Dawn*. 11 April http://www.dawn.com/news/1251409 (accessed on 26 August 2016).

Kiani, Khaleeq. 2016d. 'Power sector payables, receivables continue to grow', *Dawn*. 11 August http://www.dawn.com/news/1199526/power-sector-payables-receivables-continue-to-grow (accessed on August 26 2016).

Mohammad, Zubair Khan.2016a. 'Pakistan's biggest dam stymied by land dispute', *The Express Tribune*. 14 July http://tribune.com.pk/story/1141560/pakistans-biggest-dam-stymied-land-dispute/ (accessed on 27 August 2016).

Mustafa, Khalid. 2016. 'Circular debt continues to haunt power sector', *The News*. 5 May, https://www.thenews.com.pk/print/117604-Circular-debt-continues-to-haunt-power-sector(accessed 24 August 2016).

Pal Satyabrata. 2015. 'There's no free Chinese lunch...' *The Hindu*. 4 June http://www.thehindu.com/opinion/lead/theres-no-free-chinese-lunch/article7228058.ece(accessed on 20 August 2016).

Qandeel, Tanoli. 2016. 'Punjab gets lion's share in Chinese projects' *The Express Tribune*. 3 September. http://tribune.com.pk/story/1175160/economic-corridor-punjab-gets-lions-share-cpec-projects/ (accessed on 9 September 2016).

Radio Pakistan. 2016. '2665 MW ADDED IN SYSTEM DURING LAST 3 YEARS: KHAWAJA ASIF', 8 June , http://www.radio.gov.pk/08-Jun-2016/2665-mw-added-in-system-during-last-3-years-khawaja-asif(accessed on 26 August 2016).

Rana, Shahbaz. 2016a. 'China's security concerns: Jurisdiction issues hold up CPEC force', The *Express Tribune*. 18 October. http://tribune.com.pk/story/1201434/chinas-security-concerns-jurisdiction-issues-hold-cpec-force/ (accessed on 8 November 2016).

Rana, Shahbaz. 2016b. 'Five CPEC projects face the axe', *The Express Tribune*. 20 July http://tribune.com.pk/story/1145535/five-cpec-projects-face-axe/ (accessed 26 August 2016).

Rana, Shahbaz. 2016c. 'Pakistan waives off bidding condition for CPEC projects', *The Express Tribune*. 14 July http://tribune.com.pk/story/1122836/eccs-decisions-bidding-condition-waived-off-cpec-projects/ (accessed on 26 August 2016).

Rana, Shahbaz. 2016d. 'Power project under CPEC runs aground' *The Express Tribune*. 25 July. http://tribune.com.pk/story/1148561/power-project-cpec-runs-aground/ (accessed on 26 August 2016).

Rizvi, Jawad. 2016 'Demystifying Pakistan's energy crisis', *MIT Technology review*, http://www.technologyreview.pk/demystifying-pakistans-energy-crisis/ (accessed on 20 August 2016).

Sarfarz, Sohail. 2016. 'Projects under CPEC: Chinese authorities, FBR to discuss tax matters', *Business Recorder*. 21 June, http://www.brecorder.com/market-data/stocks-a-bonds/0:/58777:projects-under-cpec-chinese-authorities-fbr-to-discuss-tax-matters/?date=2016-06-21 (accessed on 26 August 2016).

Sayed, Baqir. 2016. 'Civil-military differences hold up CPEC security plan', *Dawn*. 19 September, http://www.dawn.com/news/1284724 (accessed on 8 November 2016).

Siddique, Sajid. 2016. 'No need to set up separate authority for CPEC: Ahsan', *Daily Times*. 19 July, http://dailytimes.com.pk/islamabad/19-Jul-16/no-need-to-set-up-separate-authority-for-cpec-ahsan (accessed on 20 August 2016).

The Economist. 2012. 'Pakistan's energy Crisis: Power Politics', 21 May, http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/05/pakistan%E2%80%99s-energy-crisis (accessed on 20 August 2016).

The Express Tribune. 2015. 'Gadani Power Project Suspended', 25 February, http://tribune.com.pk/story/843615/gadani-power-project-suspended/ (accessed on 26 August 2016).

The Express Tribune. 2016a. 'CPEC power project faces delay as land dispute drags on', 12 July, http://tribune.com.pk/story/1139715/economic-corridor-power-project-faces-delay-land-dispute-drags/ (accessed on 24 August 2016).

The Express Tribune. 2016b. 'CPEC's security', 8 September, http://tribune.com.pk/story/1178218/cpec-security/ (accessed on 9 September 2016).

The Express Tribune. 2016c. 'Major CPEC power project delayed', 12 July, http://tribune.com.pk/story/1140408/major-cpec-power-project-delayed/ (accessed on 25 August 2016).

The News. 2015. 'China to include $14 bn Diamer-Bhasha Dam in CPEC', 15 November ,https://www.thenews.com.pk/print/15683-china-to-include-14-bn-diamer-bhasha-dam-in-cpec (accessed on 26 August 2016).

The News. 2016. 'Pakistan to resume semi-annual gas tariff notification, IMF assured', 6 July https://www.thenews.com.pk/print/133277-Pakistan-to-resume-semi-annual-gastariff-notification-IMF-assured (accessed on 26 August 2016).

The Nation. 2016. 'ToRs for CPEC Special Security Div to be finalised in a week', 18 October, http://nation.com.pk/national/18-Oct-2016/tors-for-cpec-special-security-div-to-be-finalised-in-a-week (accessed on 8 November 2016).

The Wire. 2016. 'Pakistan Could End Energy Rationing in Two Years, Says Asian Development Bank', 21 June, http://thewire.in/44311/pakistan-could-end-energy-rationing-in-two-years-says-asian-development-bank/ (accessed on August 24 2016).

Zaafir Saleh, Muhammad.2016. 'Afghan refugees can stay till March: cabinet', *The News*. 10 September, https://www.thenews.com.pk/print/149244-Afghan-refugees-can-stay-till-March-cabinet (accessed 11 September 2016).

ICS ANALYSIS *Back Issues*

Issue No/ Month	Title	Author
No. 51 | Sep 2017	Public-Private Partnership in Health Care: China and India	Madhurima Nundy
No. 50 | Sep 2017	Supply Side Economics with Chinese Characteristics	Shyam Saran
No. 49 | Sep 2017	A Tale of Two Rivers: The Yangtze in Guizhou and the Mahanadi in Odisha	Anuraag Srivastava
No. 48 | Aug 2017	Lessons from the Cuban Missile Crisis for the Doklam Standoff	Rajesh Ghosh
No. 47 | Jun 2017	Engaging the Neighbours: China's Diverse Multilateralism in Central Asia	Naina Singh
No. 46 | May 2017	Regional and Sub-regional Cooperation in Health Security: India and China	Madhurima Nundy
No. 45 | May 2017	Sino-Indian Border Trade: The Promise of Jelep La	Diki Sherpa
No. 44 | Apr 2017	Comparing Indian and Chinese Engagement with their Diaspora	Gauri Agarwal
No. 43 | Nov 2016	China-Pakistan Economic Corridor: Energy and Power Play	Rishap Vats
No. 42 | Aug 2016	A Review of the 2016 Forum on the Development of Tibet	Tshering Chonzom

Principal Contributors to ICS Research Funds

TATA TRUSTS
Development Partner

सत्यमेव जयते
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA

INDIAN COUNCIL OF
SOCIAL SCIENCE RESEARCH

GARGI AND VIDYA
PRAKASH DUTT FOUNDATION

JAMNALAL BAJAJ
FOUNDATION

PIROJSHA GODREJ TRUST

ICS PUBLICATIONS

ICS ANALYSIS

A short brief on a topic of contemporary interest with policy-related inputs.

ICS OCCASIONAL PAPER

Platform for ongoing research of the ICS faculty and associates.

ICS MONOGRAPH

Authored by the faculty, also emerging from research projects and international conferences.

ICS WORKING PAPER

Draft paper of ongoing research

JOURNAL

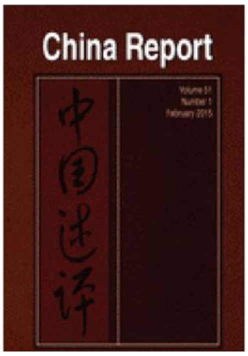

In its 54th year of publication, *China Report* is a quarterly refereed journal in the field of social sciences and international relations. It welcomes and offers a platform for original research from a multi-disciplinary perspective in new and emerging areas by scholars and research students.

INSTITUTE OF CHINESE STUDIES
8/17, Sri Ram Road, Civil Lines,
Delhi-110054, INDIA
Tel: +91 (0) 11 2393 8202
Fax: +91 (0) 11 2383 0728
http://www.icsin.org/
info@icsin.org

twitter.com/ics_delhi
In.linkedin.com/icsdelhi
youtube.com/ICSWEB
facebook.com/icsin.delhi
soundcloud.com.ICSIN
instagram.com/icsdelhi